पटना में दिनांक–14 जनवरी, 2020 मंगलवार को अपराह्न 5:00 बजे हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये:–

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

1. खरीफ विपणन मौसम 2019–20 के अन्तर्गत राज्य में धान/सी०एम०आर० अधिप्राप्ति कार्यक्रम (15, नवम्बर, 2019 से 31 जुलाई, 2020) के लिए बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को क्रियाशील पूँजी के रूप में विभिन्न व्यावसायिक बैंकों से क्रमशः वार्षिक/त्रैमासिक दर पर प्राप्त किए जाने वाले ऋण कुल 4,000/–करोड़ रूपये (चार हजार करोड़ रूपये) की राशि के लिए सरकार की गारंटी प्रदान करने की स्वीकृति के संबंध में।

1. **स्वीकृत।**

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

2. सी०डब्लू०जे०सी० संख्या 9089/2004 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 10.05.2018 को पारित न्याय निर्णय तथा एम०जे०सी० संख्या 5258/2018 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 22.10.2019 को पारित अंतरिम आदेश के आलोक में डा० रामाश्रय राम, तत्कालीन शोध पदाधिकारी (सांख्यिकी) पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, पटना की सरकारी सेवा से की गई बर्खास्तगी को सशर्त (एल०पी०ए० संख्या 447/2019 में पारित न्याय निर्णय से प्रभावित होगा) वापस लिये जाने की स्वीकृति के संबंध में।

2. **स्वीकृत।**

वाणिज्य–कर विभाग

4. बिहार कराधान विवाद समाधान नियमावली, 2020 को प्रख्यापित करने के संबध में।

4. **स्वीकृत।**

शिक्षा विभाग

5. वर्ष 2020 के अप्रैल माह से राज्य के सभी पंचायतों में कक्षा–9 के संचालन के क्रम में उच्च माध्यमिक विद्यालयविहीन पंचायतों के 2950 चिन्हित प्रारंभिक विद्यालयों में उपस्कर एवं उक्त विद्यालयों में से 1483 विद्यालयों में कक्षा–09 के संचालन हेतु 2750 अतिरिक्त वर्गकक्षों तथा शौचालय सहित अन्य सुविधाओं के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2019–20 में ₹4,09,47,23,000/–(चार अरब नौ करोड़ सैंतालीस लाख तेईस हजार रूपये) के व्यय की स्वीकृति एवं तत्काल ₹3,29,34,00,000/–(तीन अरब उनतीस करोड़ चौंतीस लाख रूपये) की विमुक्ति।

5. **स्वीकृत।**

संसदीय कार्य विभाग

6. षोडश बिहार विधान सभा के चतुर्दश–सत्र एवं बिहार विधान परिषद् के 193वें सत्र के सत्रावसान संलेख पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति के संबंध में। — 6. **स्वीकृत।**

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

8. बिहार आपूर्ति सेवा नियमावली 2007 के नियम–6 (1) में संशोधन के फलस्वरूप बिहार आपूर्ति सेवा (संशोधन) नियमावली–2020 के गठन के संबंध में। — 8. **स्वीकृत।**

उद्योग विभाग

9. बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 में संशोधन। — 9. **स्वीकृत।**

पथ निर्माण विभाग

10. पथ प्रमंडल, मुंगेर अन्तर्गत भीमबाँध वन्य प्राणी आश्रयणी क्षेत्र में कुण्डास्थान से भीमबांध वन पथ (कुल 9.554 कि०मी०) में मिट्टी कार्य, पथ परत कार्य, HP Culvert निर्माण कार्य, MInor Bridge निर्माण कार्य, Diversion कार्य सहित उन्नयन कार्य हेतु कुल 3141.80 लाख (एकतीस करोड़ इकतालीस लाख अस्सी हजार) रूपये के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — 10. **स्वीकृत।**

पथ निर्माण विभाग

11. प्रतिशत दर निविदा पद्धति में निविदित दर की न्यूनतम सीमा को तत्काल समाप्त कर परिमाण विपत्र की दर से 10 प्रतिशत से अधिक कम उद्धत दर वाले निविदा के लिए Additional Performance Guarantee के प्रावधान की स्वीकृति के संबंध में। — 11. **स्वीकृत।**

वित्त विभाग

12. दिनांक–11/12/1990 तक कार्यभारित स्थापना में नियुक्त एवं लगातार 10 वर्षों या उससे अधिक अवधि तक कार्यभारित स्थापना में कार्यरत रहने के उपरान्त पुनः दैनिक श्रमपुस्त पर प्रत्यावर्तित हुए कर्मी, जो श्रमपुस्त पर मृत/सेवानिवृत हो गये, को वित्त विभागीय संकल्प संख्या–5547, दिनांक–03/07/2019 में निहित प्रावधानों का लाभ अनुमान्य किये जाने के संबंध में। — 12. **स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

13. राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पूर्णियाँ में स्वीकृत 300 बेड के अस्पताल को 500 बेड के अस्पताल में उन्नयन के लिए भवन निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना से प्राप्त प्राक्कलन एवं तकनीकी अनुमोदन के आधार पर वित्तीय वर्ष 2019–20 में कुल रू० 87,78,24,000/–(रूपये सतासी करोड़ अठहत्तर लाख चौबीस हजार) मात्र की लागत पर स्कीम (योजना) की प्रशासनिक स्वीकृति। 13. **स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

14. इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना में वित्तीय वर्ष 2019–20 में विभिन्न विभागों को विकसित करने हेतु मशीन–उपकरण क्रय करने एवं Advance Molecular Microbiology and Molecular Genomics Lab स्थापित करने हेतु रू० 78.50 करोड़ (रूपये अठहत्तर करोड़ पचास लाख) मात्र की लागत पर स्कीम (योजना) की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति। 14. **स्वीकृत।**

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

15. राज्य योजना अन्तर्गत "जल जीवन हरियाली अभियान" के तहत वर्तमान वर्ष 2019–20 में प्रति पंचायत एक–एक कुँओं के जीर्णोद्धार हेतु निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध शुरूआती चरण में लिये गये 1068 अदद के अतिरिक्त 7319 कुँओं के जीर्णोद्धार तथा सोख्ता निर्माण की कुल ₹4567.06 लाख की योजना मात्र की राशि पर योजना स्वीकृति। 15. **स्वीकृत।**

ग्रामीण विकास विभाग

16. मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण की वर्त्तमान प्रतीक्षा सूची से छूटे हुए योग्य परिवारों तथा मुजफ्फरपुर जिला के पाँच AES प्रभावित प्रखण्डों के सभी सुयोग्य परिवारों को आवास का लाभ दिये जाने की स्वीकृति के संबंध में। 16. **स्वीकृत।**